v#.k frokjh
amethiarun@gmail.com
9868793799 @ 011&22043335

23&24 tu dk mRrj[k.M fodkl lokn

नीति आयोग ने इस नीति पर काम करना शुरु कर दिया है कि राज्य, केन्द्र की ओर ताकने की बजाय, अपने संसाधनों के विकास पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान कैसे दे ? इसके लिए नीति आयोग के दलों ने राज्यों के दौरे भी शुरु कर दिए हैं। इस नीति से किन राज्यों को लाभ होगा और कौन–कौन से राज्य घाटे में रहेंगे ? इस नीति से पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील राज्यों में विकास और पर्यावास के बीच संतुलन साधना कितना संभव होगा; यह भी एक प्रश्न है। इस नीति में राज्य से आने वाली केन्द्रीय कर राशि के आधार पर केन्द्रीय बजट में राज्य की हिस्सेदारी का विचार भी सुनाई दे रहा है। इससे आप आशंकित हो सकते हैं कि इससे कमजोर आर्थिकी वाले राज्यों में स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन की विवशता बढ जायेगी; जिसके दुष्प्रभाव व्यापक होंगे।

ये सभी प्रश्न और आशंकायें अपनी जगह सही हो सकती हैं। किंतु इस नीति के कारण, मैं स्वावलंबन और स्वनिर्णय का एक अवसर खुलता हुआ देख रहा हूं। यदि मैं इस नीति को ठीक से समझ सका हूं तो इस नीति के कारण, प्रत्येक प्रदेश को अपने भूगोल, अपने मानव संसाधन और अपनी जरूरत के मुताबिक अपने प्रादेशिक विकास का मॉडल खुद तय करने का अवसर ज्यादा खुले तौर पर मिल जायेगा।

हिमालयी राज्यों के नागरिक संगठन, लंबे अरसे से हिमालयी प्रदेशों के विकास की अलग नीति मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि नीति आयोग की यह नीति, जाने–अनजाने इसके दरवाजे खोल रही है। खुले दरवाजे का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि प्रदेश सरकारें अपने प्रदेश की सामर्थ्य, संवेदना और जरूरत का आकलन कर टिकाऊ विकास का खाका तैयार करने में जुट जाये। इस दृष्टि से उत्तराखण्ड जैसे संवेदनशाली राज्य के टिकाऊ विकास का खाका बेहद सावधानी, समझ, संवेदना, समग्रता और दूरदृष्टि की मांग करता है। इस मांग की पूर्ति के लिए ऑक्सफेम इंडिया ने साझा संवाद आयोजित करना तय किया है।

,d lk>h igy

'उत्तराखण्ड के स्थायी विकास हेतु साझी पहल' – इस शीर्षक के तहत् आयोजित यह संवाद 23–24 जून, 2015 को डायनेस्टी रिज़ोर्ट, कुरुपताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड में होगा। आप इस संवाद को 13 फरवरी, 2014 और 23 दिसम्बर, 2014 में हुए पूर्व संवादों की कड़ी में अगले कदम के रूप में देख सकते हैं।

चिंता, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने के आकलन से शुरु होती है। उत्तराखण्ड के पास न तो अपनी कोई प्रदेश स्तरीय अधिकारिक जलनीति है, न पुनर्वास नीति और न ही आपदा प्रबंधन तथा टिकाऊ विकास का कोई अधिकारिक खाका। प्राप्त आमंत्रण पत्र में उल्लिखित ऐसे कुछ संकेत स्पष्ट करते हैं कि उत्तराखण्ड शासन को चाहिए कि वह उत्तराखण्ड के निवासियों, संगठनों और विशेषज्ञों के साथ बैठकर जानने की कोशिश करे कि वे कैसा विकास चाहते हैं ? विधानसभा, जनता की राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सभा होती है। किंतु न विधानसभा ने यह कोशिश की और न ही शासन ने।

Lkk>k eap dh t:jr

ऐसा लगता है कि इस स्थिति को देखते हुए ही ऑक्सफेम इंडिया के निर्णायकों ने तय किया है कि एक ऐसा फोरम विकसित किया जाये, जो न सिर्फ टिकाऊ विकास की जनदृष्टि को सामने लाये, बल्कि आपसी सहमति विकसित करने का भी काम करे। इस फोरम के दो अन्य मकसद, उत्तराखण्ड की नीतियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने व विकास में सहभागिता के लिए नागरिक संगठनों को तैयार व एकजुट करना भी है।

फोरम में विश्वविद्यालयों, संस्थानों, विशेषज्ञों, नागरिक संगठनों, कार्यकर्ताओं, मीडिया, सेवानिवृत अधिकारियों तथा विकास के लाभार्थी पक्षों की सहभागिता पूर्व संवादों में सहमति है। संभवतः इसी दृष्टि से मुझे भी आमंत्रण प्राप्त हुआ है।

उम्मीद है कि प्रकृति की ओर से लगातार मिलते संदेशों के बीच, उम्मीदों का साझा हासिल होगा। सातत्य, सक्रियता, आपसी साझे और जवाबदेही के निजी संकल्प से ही यह संभव होता है। काश! यह हो।

dk;Zde dh le; lkj.kh lyXu gS

vf/kd tkudkjh ds fy, lEidZ %

श्री श्रीश त्रिपाठी
कार्यक्रम अधिकारी (आर्थिक न्याय)
ऑक्सफेम इंडिया, लखनऊ
फोन 0522–4172000

Consultation of Sustainable Uttarakhand

उत्तराखण्ड के स्थायी विकाश हेतु एक साझी पहल

23rd & 24th June, Nainital

Agenda

Time	Session topic	Facilitators	Expectations/session objectives
23rd June 2015, Day 1			
9.00 to 9.30	Registration		
9.30 to 9.45	Welcome Speech & Introduction to the workshop	Nand Kishor Singh	Welcome, Expectation of participants & sharing Workshop objectives and expectations
9.45 to 10.30	Introduction & Ice breaking	Shreesh	Introduction of participants
10.30 to 11.00	Context setting	Dr. Ravi Chopra	Recap of the sustainable development issues identified through the study
11.00 to 11.30		Shreesh Tripathi	Sustainable development concerns in polices & practices
11.30 to 11.45	Tea Break		
11.45 to 12.30	Open house	Shreesh tripathi	Clarification on presentation, Question & answer, sharing from few participants
12.30 to 13.30	Breakout sessions for Sub Group Discussions	Sub group moderators	Identification of key advocacy issues & concerns through sub group discussions on core thematic areas & developing Strategy for collective advocacy
13.30 to 14.30	Lunch		
14.30 to 15.30	Break out session for sub group discussions	Sub group moderators	
15.30 to 16.45	Finalization of key	Fish bowl	Finalization of key advocacy agenda

	issues & strategy in fish bowl	moderators	for one year & advocacy strategy
16.45 to 17.00	Tea Break		
17.00 to 17.45	Presentation by moderators	Panel members	Group moderators will present the group decision on issues & Strategy
17.45 to 18.30	Finalization of key advocacy agenda & strategy	Panel members	Developing consensus on advocacy issues & strategy
18.30 to 18.45	Feedback on the day	Shreesh	

24th June 2015, Day 2			
9.00 to 9.15	Recap & reflection	Open house	
9.15 to 9.30	Progress made so far on Uttarakhand Sustainable Development Forum (USDF)	Shreesh	Bringing all participants on page on collective advocacy through USDF
9.30 to 10.45	structure & ways of working of USDF	Sub group moderators	3 sub groups discusses & presents their idea on USDF
10.45 to 11.30	Presentation by sub groups & discussions	Sub group representatives	Sub groups presents their ideas & discussion in the panel
11.30 to 11.45	Tea Break		
11.45 to 12.30	Finalization by panel	Panel members	Structure, membership & ways of working is finalized
12.30 to 13.00	Road ahead & action plan	Panel members	Finalization of roadmap on taking forward the advocacy agendas through collective efforts, roles & responsibility sharing, committee formation etc.
13.00 to 13.15	Feedback	Open house	
13.15 to 13.30	Way forward & Thanks giving	Sabita/Farrukh	
13.30 to 14.30	Lunch break & departure		